the stand taken by the managements of the banks.

The policy of the Government is always to sort out the issues raised by the employees through mutual discussions. It was in this spirit that agreements were reached on pension and computerisation in the banking industry at a huge cost of Rs. 500 crores annually.

**Increase in Power Supply to Andhra Pradesh**

*717. DR ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government hae any plans to increase power supply to Andhra Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have plans to increase finance to Ramagudam Thermal Power Station; and

(d) what is the present quantum?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE): (a) and (b) Government's plan to increase power supply to Andhra Pradesh is as under :—

(i) Allocation for Andhra Pradesh from the unallocated output of the Central Sector Stations in the Southern region has been enhanced from 25 per cent to 50 per cent w.e.f. 1-3-1994.

(ii) Assistance from Western Region is being provided to Andhra Pradesh.

(iii) A capacity addition of 1303.6 MW has been targetted during 8th Plan period for Andhra Pradesh.

The other measures taken to increase the power supply to the State of Andhra Pradesh include maximising of generation from existing units, reduction in T&D losses, implementation of better demand management and energy conservation measures etc.

(c) and (d) At present capacity of NTPC Ramagundam Theremal Power Station is 2100 MW. Presently there is no proposal to increase capacity requiring additional finance at this station. Future proposals however include installation of additional 500 MW capacity at NTPC Ramagundam STPS and installation of 2 Units of 250 MW each at APSEB's Ramagundam TPS Extension.

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों की घाटे में चल रही शाखाएं**

*718. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : श्रीमती सुषमा स्वराज

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों की ऐसी 104 शाखाओं की पहचान की है जो निरन्तर घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ऐसी शाखाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इनमें कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(घ) क्या सरकार इन बैंक शाखाओं का भविष्य में कार्य संचालन करने हेतु कोई स्पष्ट नीति अपना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इन शाखाओं को हर वर्ष औसत कुल कितनी राशि का घाटा हो रहा है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)** : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान हानि उठाने वाली 28 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 13232 थी। माननीय संसद सदस्यों ने जिन 104 शाखाओं का जिक्र किया है वे राष्ट्रीयकृत बैंकों की वे शाखाएं हैं जिन्हें बैंकों द्वारा दिसम्बर 1993 में भारतीय रिजर्व बैंकों को प्रस्तुत किए गए समझौता ज्ञापन में बंद करने या उनका विलय करने/के लिये पता लगाया गया है।

जिन शाखाओं को बंद करने/उनका विलय करने के लिये पता लगाया गया है उनका बैंक-वार ब्यौरा क्या है नीचे दिया गया है :—